किसानों के हितों के अनुरूप जैव ईंधन लक्ष्यों का पुनर्समायोजन: नीतियों में त्वरित सुधार की आवश्यकता

कृष्ण बीर चौधरी

अध्यक्ष, भारतीय कृषक समाज सदस्य, एमएसपी एवं कृषि मुद्दों पर उच्च स्तरीय समिति (भारत सरकार)

भारत के महत्वाकांक्षी इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य के साथ, देश ने इथेनॉल उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि देखी है, जो अब घरेलू माँग से अधिक हो गई है। भारत सरकार की सशक्त नीतिगत प्रेरणा और हमारे किसानों की उतनी ही उत्कृष्ट प्रतिक्रिया के कारण यह 20 प्रतिशत ईबीपी का लक्ष्य समय से पहले हासिल हो सका। अब समय आ गया है कि बदले हुए परिदृश्य के अनुरूप इथेनॉल नीति को अधिक संवेदनशील बनाकर किसानों के हितों की रक्षा की जाए।

वर्तमान में, पेट्रोल में लगभग 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य पूरा करने के बाद भारत के पास 930 करोड़ लीटर की अधिशेष इथेनॉल उत्पादन क्षमता है। अक्टूबर 2025 तक, इथेनॉल उत्पादन क्षमता 1953 करोड़ लीटर थी, जबकि लगभग 20% मिश्रण के लिए खरीदा गया इथेनॉल 1023 करोड़ लीटर था।

इथेनॉल के अधिशेष अधिशेष उत्पादन के कारण, अनेक इथेनॉल डिस्टिलरियाँ अपनी अधिकतम क्षमता पर नहीं चल पा रही हैं। वर्तमान में भारत में 499 इथेनॉल डिस्टिलरियाँ संचालित हो रही हैं, जिनमें से अधिकांश अपनी क्षमता से कम पर चल रही हैं। कुछ तो 40%

से भी कम क्षमता पर चल रही हैं। यह क्षमता से कम उपयोग किसानों से कच्चे माल की कम खरीद का कारण बन रहा है, जिससे बाज़ार में अतिपूर्ति की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उदाहरण के लिए, एक वर्ष पहले खुले बाज़ार में मक्के की कीमत लगभग 2,500 प्रति क्विंटल थी, जो भारत सरकार द्वारा घोषित 2,400 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक थी; तब से यह गिरकर 1,500 प्रति क्विंटल हो गई है, जो एमएसपी से काफी नीचे है और मक्का किसानों को गंभीर वित्तीय संकट में डाल रही है।

इथेनॉल डिस्टिलरियों के कम उपयोग के कारण गन्ना किसान भी संकट में हैं। 2018 में भारत सरकार ने इथेनॉल को चीनी उद्योग का एक महत्वपूर्ण राजस्व-अर्जक उप-उत्पाद बनाया। तब से गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 39% बढ़कर 255 प्रति क्विंटल से 355 प्रति क्विंटल हो गया। इससे देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों की आय में वृद्धि हुई। वर्तमान में, गन्ना भारत की इथेनॉल खपत में 30% का योगदान देता है। डिस्टिलरियों में बिना बिके इथेनॉल का भंडार गन्ना किसानों के भुगतान में देरी कर रहा है, जिससे पुनः कृषक समुदाय संकट में पड़ रहा है।

इसी प्रकार, भारत अपनी वार्षिक घरेलू माँग से अधिक चावल उत्पादन करता है, और इस अधिशेष का उपयोग तेज़ी से इथेनॉल उत्पादन के लिए किया जा रहा है। इस विकास का अनाज किसानों की आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि इससे पारंपरिक बाज़ारों पर उनकी निर्भरता कम हो रही थी और उन्हें अच्छा प्रतिफल भी मिल रहा था। हालाँकि, डिस्टिलरी क्षमता के कम उपयोग के कारण अनाज की कीमतों में तीव्र गिरावट आ रही है और अन्य अनाजों का इथेनॉल फीडस्टॉक के रूप में उपयोग भी सीमित हो रहा है।

इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के लिए कच्चे माल के अधिशेष उत्पादन के संदर्भ में भारतीय किसानों की यह उपलब्धि भारत को खाद्य और ईंधन सुरक्षा की दिशा में सहायता कर रही है, और

इसे एक सशक्त नीतिगत प्रोत्साहन द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए जो किसानों से कच्चे माल की खरीद की गुंजाइश बनाए और उन्हें समृद्धि के मार्ग पर बनाए रखने में सहायता करे। भारतीय कृषक समाज निम्नलिखित नीतिगत उपायों का सुझाव दे रहा है।

निर्यात का लाभ उठाना और नए बाज़ारों का विकास

अधिशेष इथेनॉल का निर्यात कीमतों को स्थिर कर सकता है और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कर सकता है। लक्षित बाज़ारों में दक्षिण-पूर्व एशिया, यूरोप और अफ्रीका (जैव ईंधन की बढ़ती माँग वाले क्षेत्र) तथा वे देश शामिल हो सकते हैं जिनके साथ भारत मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर वार्ता कर रहा है। इन नए बाज़ारों में अनुमानित निर्यात क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 930 करोड़ लीटर इथेनॉल हो सकती है।

पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाना

सरकार को पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 27 प्रतिशत तक पहुँचाने के लक्ष्य में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को प्राथमिकता के आधार पर E27 ईंधन के लिए मानक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य को शीघ्र से शीघ्र गति प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। नए वाहनों के पंजीकरण के लिए E20 एवं उच्चतर ईंधन के अनुकूल वाहनों हेतु एक नीति को अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता है।

एक इथेनॉल मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की जाए जिसमें एक बफर स्टॉक तंत्र शामिल हो, जो अधिशेष उत्पादन को अवशोषित करे और मूल्यों को स्थिर रखे, साथ ही किसानों की आय की सुरक्षा के लिए इथेनॉल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाए।

भुगतान तंत्र को सुदृढ़ किया जाए — इसके लिए प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली लागू की जाए जो यह सुनिश्चित करे कि किसानों को गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त हो, और भुगतान में विलंब करने वाली चीनी मिलों पर दंड का प्रावधान किया जाए।

इथेनॉल व्युत्पन्न बाजार का विकास

इथेनॉल से एथिल एसीटेट, एथिलीन और बायोप्लास्टिक के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल व्युत्पन्न बाजार का विकास किया जाना आवश्यक है। इससे किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए आय के नए स्रोत सृजित होंगे।

ये नीतिगत उपाय भारत में इथेनॉल बाजार को स्थिर करने में सहायक होंगे, कच्चे माल का सुदृढ़ उत्पादन आधार तैयार करेंगे तथा मूल्य श्रृंखला के साझेदारों को उस तनाव से मुक्ति दिलाएंगे जिससे वे वर्तमान में गुजर रहे हैं।

इथेनॉल: किसानों के लिए नया अग्रणी व्यावसायिक अवसर

इथेनॉल उत्पादन ने भारत में किसान समुदाय के लिए पर्याप्त आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय लाभ प्रदान किए हैं — जिनमें आय में उल्लेखनीय वृद्धि, रोजगार सृजन, फसल विविधीकरण तथा ग्रामीण समृद्धि को प्रोत्साहन सम्मिलित हैं।

इथेनॉल उत्पादन ने गन्ना, मक्का और अधिशेष अनाज जैसी फसलों के लिए एक विश्वसनीय नया बाजार सृजित किया है, जिससे कृषि द्वार मूल्य (फार्म गेट प्राइस) स्थिर होते हैं और भाग लेने वाले किसानों की आय में वृद्धि होती है। हाल के वर्षों के आंकड़े दर्शाते हैं कि इथेनॉल की उच्च खरीद दरों के कारण गन्ना और मक्का किसानों की वार्षिक आय में 15–18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर, बिहार के मक्का किसान उन राज्यों के किसानों की तुलना में प्रति हेक्टेयर 2,500–3,000 अधिक अर्जित कर रहे हैं, जहाँ इथेनॉल उत्पादन का अभाव है।

इस क्षेत्र ने किसानों को 1.04 लाख करोड़ से अधिक के भुगतान को सुगम बनाया है, जिससे ग्रामीण आय तथा वित्तीय स्थिरता — विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे चीनी पेटी क्षेत्रों में — में उल्लेखनीय सुदृढ़ता आई है।

रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास

इथेनॉल उत्पादन सुविधाओं और अवसंरचना के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। प्रति करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन से कृषि मूल्य श्रृंखला (एग्रीकल्चरल वैल्यू चैन) के साथ लगभग 290 प्रत्यक्ष और 1,280 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होते हैं।

विभिन्न राज्यों में नई डिस्टिलरी और लॉजिस्टिक्स रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, जो व्यापक ग्रामीण जैव-अर्थव्यवस्था को सहारा प्रदान करते हैं तथा सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता को कम करते हैं।

फसल विविधीकरण और मूल्य स्थिरता

इथेनॉल कार्यक्रम वैकल्पिक फीडस्टॉक जैसे मक्का, मीठी ज्वार और बायोमास की खेती को प्रोत्साहित करके फसल विविधीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे किसानों को जोखिम प्रबंधन में सहायता मिलती है और उनकी आय अधिक स्थिर होती है। अधिशेष एवं क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के अवशोषण से बाजार में अतिरेक की स्थिति को रोका जाता है, मूल्य स्थिर रहते हैं, खाद्य सुरक्षा नीति के लक्ष्यों को समर्थन मिलता है तथा अपव्यय में कमी आती है।

पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव

ईंधन में इथेनॉल उत्पादन और मिश्रण से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है, लगभग 700 लाख टन CO समतुल्य उत्सर्जन को टाला गया है तथा भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को समर्थन मिला है।

द्वितीय पीढ़ी (2G) इथेनॉल उत्पादन कृषि अपशिष्ट को एक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करके किसानों को महत्त्वपूर्ण आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है। इससे आय के नए स्रोत सृजित होते हैं, फसल अवशेष दहन की समस्या का समाधान होता है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

वित्तीय लाभ

किसान धान एवं गेहूं की पराली, गन्ने की खोई और मक्के के डंठल जैसे कृषि अवशेषों को जैव ईंधन संयंत्रों को बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करते हैं। यह 'अपशिष्ट से समृद्धि' का दृष्टिकोण एक पूर्व निपटान समस्या को लाभकारी अवसर

में परिवर्तित कर देता है।

अपने अधिशेष बायोमास को बेचकर किसान कृषि अपशिष्ट को जलाने अथवा अन्य प्रकार से निपटाने से जुड़ी लागतों की भरपाई कर सकते हैं अथवा उन्हें पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं।

फसल के सभी भागों का उपयोग करने से किसान अपनी समग्र उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं और अपनी भूमि से अधिकतम प्रतिलाभ (रिटर्न्स) प्राप्त कर सकते हैं।

सरकारी खरीद नीतियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्य गारंटी और मिश्रण लक्ष्यों जैसे 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के मील के पत्थर — ने किसानों के लिए बाजार पहुँच और उचित प्रतिलाभ सुनिश्चित किए हैं।

ब्याज अनुदान, अवसंरचना निवेश और फीडस्टॉक विविधीकरण समर्थन जैसी विशेष योजनाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और कृषि आय में और अधिक वृद्धि को प्रोत्साहित किया है।

इथेनॉल खरीद ने भारत में किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है — इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हजारों करोड़ रुपये में मापा गया है तथा गन्ना और मक्का किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर लाभ में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

समग्र प्रत्यक्ष आय वृद्धि

चीनी सीजन 2023–24 में अकेले इथेनॉल खरीद से किसानों को किए गए भुगतान 1,11,703 करोड़ से अधिक रहे, जबकि चालू वर्ष में, जब भारत 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, किसानों को सीधे लगभग 40,000 करोड़ के भुगतान की अपेक्षा है।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के आरंभ से अब तक इथेनॉल आपूर्ति से किसानों की संचयी आय 1,21,000 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जो ग्रामीण नकद प्रवाह में नाटकीय वृद्धि और समय पर भुगतान को दर्शाती है, विशेष रूप से गन्ना उत्पादकों के संदर्भ में।

अनाज आधारित इथेनॉल खरीद, विशेष रूप से अधिशेष मक्का और चावल से अनाज किसानों को प्रत्यक्ष भुगतान के रूप में प्रति वर्ष अतिरिक्त 35,000 करोड़ सृजित होने का अनुमान है, क्योंकि प्रतिवर्ष 165 लाख मीट्रिक टन अधिशेष अनाज इथेनॉल उत्पादन में उपयोग किया जाता है।

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख राज्यों के गन्ना किसानों की वार्षिक आय में 15–18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब इथेनॉल की माँग प्रबल होती है, तब गन्ना खेती से शुद्ध लाभ लगभग 40,000 प्रति हेक्टेयर तक पहुँच जाता है, जो इथेनॉल से असंबद्ध बाजारों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है।

इथेनॉल डिस्टिलरीज को आपूर्ति करने वाले राज्यों के मक्का किसानों को उन क्षेत्रों के किसानों की तुलना में प्रति हेक्टेयर 2,500–3,000 की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है, जहाँ इथेनॉल खरीद की व्यवस्था नहीं है। इथेनॉल आपूर्ति के लिए जीएसटी और परिवहन प्रभार अलग से भुगतान करने की सरकार की पहल यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को समर्थन मूल्य और समय पर खरीद के अतिरिक्त उच्चतर प्रभावी आय भी प्राप्त हो।

भविष्य की राह

पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, यदि इथेनॉल मिश्रण 20 प्रतिशत तक पहुँच जाता है, तो भारतीय किसानों को इथेनॉल खरीद से प्रत्यक्ष भुगतान के रूप में प्रति वर्ष लगभग 40,000–45,000 करोड़ अर्जित होने का अनुमान है, जो कृषि समुदाय के लिए एक अभूतपूर्व लाभांश होगा।

ये भुगतान कृषि परिवारों की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि करते हैं, जिससे व्यय क्षमता में सुधार, ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि और सरकारी सहायता अथवा सब्सिडी पर निर्भरता में कमी आती है।

अनाज आधारित इथेनॉल विशेष रूप से मक्का और अधिशेष चावल की ओर विविधीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि भुगतान का लाभ गन्ना पेटी क्षेत्रों और नवीन भागीदार क्षेत्रों में समान रूप से वितरित हो, जिससे ग्रामीण प्रभाव का दायरा और विस्तृत हो।

फसल प्रकार के अनुसार राजस्व विभाजन

गन्ना: यह इथेनॉल फीडस्टॉक का सबसे बड़ा घटक है, जो चीनी उद्योग के साथ दीर्घकालिक संबंध के कारण सामान्यतः लगभग 70–75 प्रतिशत का योगदान करता है। वार्षिक रूप से किसानों को अनुमानित कुल 40,000–45,000 करोड़ के राजस्व में से गन्ना किसानों को प्रति वर्ष 28,000–34,000 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है।

मक्का: जैसे-जैसे सरकार गन्ने के साथ-साथ अनाज आधारित इथेनॉल को बढ़ावा दे रही है, मक्का का योगदान भी बढ़ता जा रहा है। हाल के अनुमानों के अनुसार, मक्का कुल इथेनॉल उत्पादन में लगभग 15–18 प्रतिशत का योगदान कर सकता है, जो 20 प्रतिशत पूर्ण मिश्रण की स्थिति में वार्षिक किसान राजस्व के रूप में 6,000–8,000 करोड़ में परिवर्तित होगा।

अधिशेष खाद्यान्न (चावल/गेहूं/टूटा चावल): सरकारी भंडार और एफसीआई, खरीद से इथेनॉल के लिए पुनर्निर्देशित अधिशेष एवं क्षतिग्रस्त अनाज फीडस्टॉक का 7–10 प्रतिशत योगदान कर सकते हैं, जिससे कृषि राजस्व में प्रति वर्ष 3,000–4,500 करोड़ का समर्थन प्राप्त होगा।

20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के मील के पत्थर पर अधिकांश किसान राजस्व गन्ना उत्पादकों को प्राप्त होगा, परंतु फीडस्टॉक विविधीकरण में तेजी आने के साथ-साथ मक्का और अधिशेष अनाज किसानों की आय में भी तीव्र वृद्धि होना निश्चित है। यह प्रवृत्ति इथेनॉल मूल्य श्रृंखला के विस्तार के साथ अधिक क्षेत्रों और फसल प्रकारों में आय को प्रोत्साहित करेगी।